✦ वर्ष-5 ✦ अंक-02 ✦ जुलाई- 2024 ✦ बालोद (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित ✦ पृष्ठ-32

मासिक पत्रिका

RNI-CHHHIN/2021/82341

प्रदेश रुचि

30 ₹

सच्ची खबर,पक्की खबर

उम्मीदों का बजट

केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण : सीएम साय

2 Kargil Hero की प्रेम कहानी

नगरवासियों के सपनों के अनुरूप राजनांदगांव शहर का होगा विकास : डॉ. रमन सिंह

नन्हें बच्चों से मिलकर मुग्ध हुए रमन सिंह

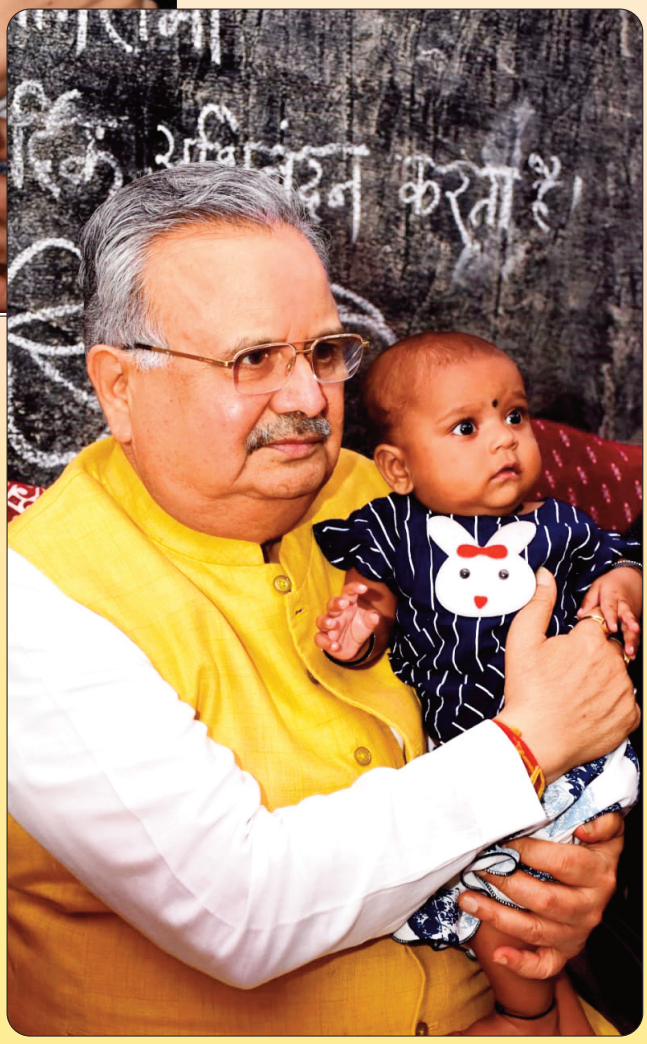

राजनांदगांव (प्रदेश रुचि). विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज राजनांदगांव विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला बरगा पहुंचकर स्कूल के बच्चों एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के नन्हें बच्चों से मिलकर मुग्ध हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने नन्हें बच्चों को गोदी में लेकर दुलार किया तथा उनके अभिभावकों को बच्चों को पौष्टिक आहार देने की समझाईश दी। उन्होंने जिले में संचालित पोट्टु लईका पहल के संबंध में जानकारी ली तथा सुपोषित बच्चों की माताओं को शाल-श्रीफल देकर सम्मानित किया। उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे आहार के संबंध में माताओं से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों को वजन बढ़ाने के लिए जागरूकता के साथ कार्य करें तथा गुणवत्ता-पूर्ण पौष्टिक भोजन दें। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए जिले में संचालित पोट्टु लईका पहल के संबंध में जानकारी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्तर पर जिले को एक युद्ध नशे के विरूद्ध अभियान अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्राथमिक शाला बरगा में संपर्क डिवाईस के माध्यम से अध्ययन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट टीवी के माध्यम से संपर्क डिवाईस में निहित कविताओं एवं अन्य अध्ययन सामग्री से बच्चे शीघ्रता से सीखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों के साथ मिलकर भारत माता की जय, वन्देमातरम् का उद्घोष किया और उन्हें अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री अशोक देवांगन, श्री सुर्यकांत भंडारी, श्रीमती प्रतीक्षा भंडारी, श्रीमती पुष्पा गायकवाड़, श्री कुमार सोनवानी, श्री लीलाधर साहू, श्री रोहित चंद्राकर, अन्य जनप्रतिनिधि, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, जिला पचांयत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा सहित, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अभय जायसवाल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती गुरप्रीत कौर, जिला मिशन समन्वयक श्री सतीश ब्यौहारे, अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

मासिक पत्रिका
प्रदेश रुचि
सच्ची खबर,पक्की खबर
RNI-CHHHIN/2021/82341
जुलाई-2024 (मासिक)
● वर्ष-5 ● अंक-02
● पृष्ठ-32
बालोद (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित
मूल्य 30/-
संपादक
संतोष कुमार साहू
सलाहकार संपादक
मोहनदास मानिकपुरी
रमन टुवानी
छायाकार
तनवीर आलम
विशेष सहयोग
नरेश श्रीवास्तव
ले-आउट
संजय (9669576496)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **संतोष कुमार साहू**, द्वारा मयंक आफसेट, कंकाली तालाब के सामने, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)से मुद्रित कर हाऊस नं. 192/2, स्टेशन रोड, पाररास, जिला-बालोद (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित
- संपादक -
*** संतोष कुमार साहू**
*** पी.आर.बी.एक्ट के तहत समस्त समाचार/लेखों के चयन के लिए जिम्मेदार**
मोबाईल-9893162815,7000553221
E-mail- pradeshruchi@gmail.com
*(सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र बालोद होगा)

बजट

10

बजट को लेकर मिली अलग अलग प्रतिक्रिया

11

कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ बन गया था अपराध गढ़ : किरण देव

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पीएमओ ने दिया जवाब- पेज-11

13

छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

15

अटल जी ने पृथक राज्य बनाकर दिया, इसे संवारने की जिम्मेदारी हमारी : मुख्यमंत्री

गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार सख्त

अपने काम को पूरी ईमानदारी और दक्षता से करना ही देशसेवा: मुख्यमंत्री साय

संपादक की कलम से

शिक्षित होना ही काफी नहीं है...

संतोष कुमार साहू

आम तौर पर माना जाता है कि अच्छी जिंदगी के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षित आदमी ही अपना, परिवार,समाज व देश का भला बुरा समझ सकता है। आदमी शिक्षित है तो उसे नौकरी तो मिल ही जाएगी। शिक्षा के लिए स्कूल क़ॉलेजों की अब कोई कमी नहीं है देश में इसलिए हर साल करोड़ों शिक्षित बेरोजगार बढ़ जाते हैं यानी हर साल देश व राज्यों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जाती है। सारे पढ़े लिखे लोग सरकारी नौकरी ही चाहते हैं और सरकारी नौकरी कम होने के कारण केंद्र व राज्य सरकार इनको नौकरी नहीं दे सकते। सरकारी नौकरी कम होने से भी अब सबकों सरकारी नौकरी मिलती नहीं है।बेरोजगारी गंभीर समस्या हो चुकी है। इसका समाधान जरूरी हो गया है। हर राजनीतिक दल चुनाव में इसे बड़ा मुद्दा बनाता है इससे राजनीतिक दलों को चुनाव में फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और उसका उसे कुछ फायदा भी हुआ। सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मोदी सरकार को यह बात समझ में आ गई कि देश का तेजी से विकास करना ही काफी नहीं है यदि विकास के साथ देश के युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो ऐसी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था किस काम की है। यदि देश में शिक्षित युवाओं की आबादी बढ़ रही है और उनको रोजगार के लायक नहीं माना जाता है तो ऐसे शिक्षित बेरोजगार देश व परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। देश को अब ऐसे विकास की जरूरत है जिससे साथ साथ ही रोजगार भी पैदा हो। साथ ही देश को ऐसे शिक्षित बेरोजगारों की जरूरत है जितको कोई काम आता हो। देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव 1990 में किया गया. तब भी बेरोजगारी समस्या थी, तब माना गया था कि देश जैसे जैसे विकास करेंगा, बेरोजगारी की समस्या भी हल होती जाएगी यानी लोगों को ज्यादा रोजगार भी मिलेगा। लेकिन तीन दशक बाद ही देश के लोगों का यह एहसाल होने लगा था कि अब जो विकास हो रहा है, वह रोजगार पैदा करने वाला विकास नहीं है। यानी विकास व रोजगार का कोई सीधा संबंध नहीं रह गया ,था क्योंकि जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उतने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। नई नई तकनीक हर क्षेत्र में आने से भी रोजगार के अवसर कम होते गए हैं। नई नई मशीने आ जाने से अब रोजगार के लिए जरूरी हो गया कि हर तरह की मशीन पर काम करना आता है तो रोजगार मिलेगा। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था आजादी के सात दशक बाद भी युवाओं को डिग्री देने वाली है,काम के लायक बनाने वाली नही है। वर्तमान में डिग्री वाले युवा को नौकरी भले न मिले लेकिन जिसे कोई काम आता है उसे नौकरी जरूर सरकारी नहीं तो निजी क्षेत्र में नौकरी मिल जाती है। अब तो यह कहा जाता है कि नौकरी तो बहुत है लेकिन नौकरी के लायक युवा नहीं है। अब नौकरी के लिए स्किल जरूरी है। स्किल है तो अवसर मिलना चाहिए। वक्त को देखते हुए मोदी सरकार ने पहली बार रोजगार की दिशा में बजट में पांच ऐसी योजनाओं की घोषणा की है जिससे युवाओं को नौकरी के लिए जिस तरह के प्रशिक्षण की जरूरत है, वह संस्थाओं में दिया जाएगा। इसकी शुरुआत तो देश में हो गई थी लेकिन प्रशिक्षित लोगों को काम नहीं मिल रहा था तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही सरकारी सहित निजी कंपनियों में काम करने व काम सीखने का अवसर मिलना चाहिए। किसी सरकार ने कभी कोशिश नहीं की इसलिए निजी क्षेत्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ। मौदी सरकार ने देश की पांच सौ बड़ी कंपनियो से युवाओं को काम करने देने व काम सिखाने के लिए बात की है। इसके लिए सरकार ने युवाओं को पैसे देने के साथ ही कंपनियों को भी आथिक सहयोग देने का फैसला किया है। इससे आने वाले दिनों में देश में जितना विकास होगा, उसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी पहले से ज्यादा होंगे क्योंकि देश में पहली बार विकास से रोजगार को सीधे जोडने की कोशिश की गई है। मोदी सरकार जिस तरह से भी देश में रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है, उस तरह से बढावा देने जुटी हुई है।रोजगार के लिए युवाओं को जिस तरह का सहयोग चाहिए मोदी सरकार मुहैया कराने का प्रयास करती रही है। इस बार के बजट में भी ऋण से लेकर हर तरह के सहयोग देने की घोषणा की गई है। मोदी सरकार चाहती तो अन्य दलों की सरकार की तरह बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर सकती थी,उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि इसमें पैसा तो खर्च होता है लेकिन देश का युवा देश के काम के लायक नहीं बनता है। मोदी सरकार की कोशिश देश के युवाओं को देश के काम के लायक बनाने की है ताकि वह देश के विकास में सहयोग कर सकें।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया है। बजट में नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा।

नया टैक्स रिजीम

अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये या उससे अधिक है तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको 17,500 रुपये का फायदा होगा। टैक्स में कमी से हेल्थ और एजुकेशन सेस भी कम हो जाता है। इससे आप 700 रुपये (17,500 रुपये का 4%) और बचा सकते हैं। इस तरह आपकी कुल बचत 18,200 रुपये हो जाती है। अगर आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच है, तो आप सरचार्ज पर 1,750 रुपये (17,500 का 10%) बचाएंगे। इससे आपकी कुल बचत 20,020 रुपये हो जाएगी। इसी तरह सालाना एक से 2 करोड़ रुपये के बीच इनकम वाले टैक्सपेयर्स को 15% सेस के साथ 20,930 रुपये की बचत होगी। डिविडेंड और कैपिटल गेन को छोड़कर 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये के बीच 25% सेस का मतलब है कि आपकी कुल बचत 22,750 रुपये होगी। डिविडेंड और कैपिटल गेन को मिला लिया जाए तो 15% सेस के साथ आप 20,930 रुपये बचाएंगे।

पुराना टैक्स रिजीम

अगर आपने पुराने टैक्स रिजीम को चुना है तो बजट में की गई घोषणाओं से आपके टैक्स कैल्कुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन में हुई बदलाव के कारण आप नुकसान में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए इक्विटी पर शॉर्टटर्म गेन पर अब 15% के बजाय 20% टैक्स लगेगा। यदि आप एक साल में शेयरों की खरीद-फरोख्त से 2 लाख रुपये कमाते हैं, तो आपको 30,000 रुपये के बजाय 40,000 रुपये देने होंगे। इसी तरह दो साल से अधिक समय तक रखी गई प्रॉपर्टी की बिक्री पर भी आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें होने वाले फायदे पर अब 20% के बजाय 12.5% टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें पेच यह है कि आपको इनडेक्सेशन बेनिफिट का फायदा नहीं मिलेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवर को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स समाप्त करने और नई कर प्रणाली के तहत कर दरों में बदलाव करने का भी एलान किया है। वित्त मंत्री ने पहली बार नौकरी करने वालों को भी राहत देने से जुड़ी घोषणाएं की हैं।

पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा

सरकार की नौ प्राथमिकताओं में से एक है रोजगार और कौशल विकास। इसके तहत पहली बार नौकरी करने वालों को बड़ी मदद मिलने जा रही है। फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।

पीएफ में एक महीने का योगदान सरकार देगी

सरकार रोजगार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को भी फायदा देने जा रही है। यह फायदा भविष्य निधि यानी पीएफ में एक महीने के योगदान के रूप में होगा।

एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता

वित्त मंत्री निर्मण सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसमें युवाओं को कारोबार के वास्तविक माहौल को जानने और अलग-अलग पेशे की चुनौतियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। यही नहीं, उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।

नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव

नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से चार करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से 10 लाख से ज्यादा वेतन पाने वालों को 17,500 रुपये की बचत होगी। नई कर प्रणाली में टैक्स स्लैब इस तरह से तैयार किया गया है।

शून्य - 3 लाख रुपये - 0

3 से 7 लाख रुपये -	**5%**
7 से 10 लाख रुपये -	**10%**
10 से 12 लाख रुपये -	**15%**
12 से 15 लाख रुपये -	**20%**
15 लाख से ज्यादा -	**30%**

म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर अब नहीं लगेगा टीडीएस

चैरिटी के मामलों में दो अलग-अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। विभिन्न भुगतान के लिए पांच फीसदी टीडीएस की जगह दो फीसदी टीडीएस की व्यवस्था होगा। म्यूच्युअल फंड्स या यूटीआई के री-पर्चेस पर 20 फीसदी टीडीएस को वापस ले लिया गया है। ईकॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए टीडीएस को एक फीसदी से घटाकर 0.1

फीसदी कर दिया गया है।

पीएम गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ी

हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था

मोबाइल फोन और उपकरण सस्ते होंगे

वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन और उपकरणों के सस्ते होने से जुड़े एलान किए हैं। उन्होंने कहा कि घरेलू उत्पादन में इजाफा हुआ है। इस कारण मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया जाएगा। घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसकी समग्र समीक्षा की जाएगी ताकि इसे और आसान किया जा सके।

कैंसर की तीन और दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से मुक्त किया गया

वित्त मंत्री ने कैंसर के मरीजों के लिए तीन और दवाओं को पूरी तरह सीमा शुल्क से मुक्त करने का एलान किया है। इसके साथ ही एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाने का एलान किया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क छह फीसदी और प्लेटिनम पर 6.4 फीसदी घटाया गया

बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये

बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी।

वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र से जुड़े जरूरी एलान किए

वित्त मंत्री ने पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान रहने ही बात अपने बजट भाषण में कही है। उन्होंने महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण के एलान की बात कही है। गया के विष्णुपद मंदिर में भी कॉरिडौर बनाया जाएगा। यह काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर जैसे ही होंगे राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करेगी। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इ

आम बजट में सरकार ने नौ प्राथमिकताएं गिनाईं

1. खेती में उत्पादकता
2. रोजगार और क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अधोसंरचना
8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार

देश में रोजगार पैदा करने सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी

मोदी सरकार 3.0 ने अपने पहले बजट में युवाओं और रोजगार पर पूरा फोकस किया है। सरकार पर लगातार रोजगार को लेकर सवाल उठते रहे हैं, ऐसे में बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ा एलान किए हैं। सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार शानदार वृद्धि हो रही है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर सरकार का पूरा फोकस है। रोजगार, कौशल, MSME, मिडिल क्लास पर लागातर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार सरकार का फोकस रोजगार पैदा करने पर है। इन स्कीम से देश के 20 लाख युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव की 3 स्कीम लाई जाएंगी। PM योजना के तहत 3 चरणों में इंसेंटिव दिया

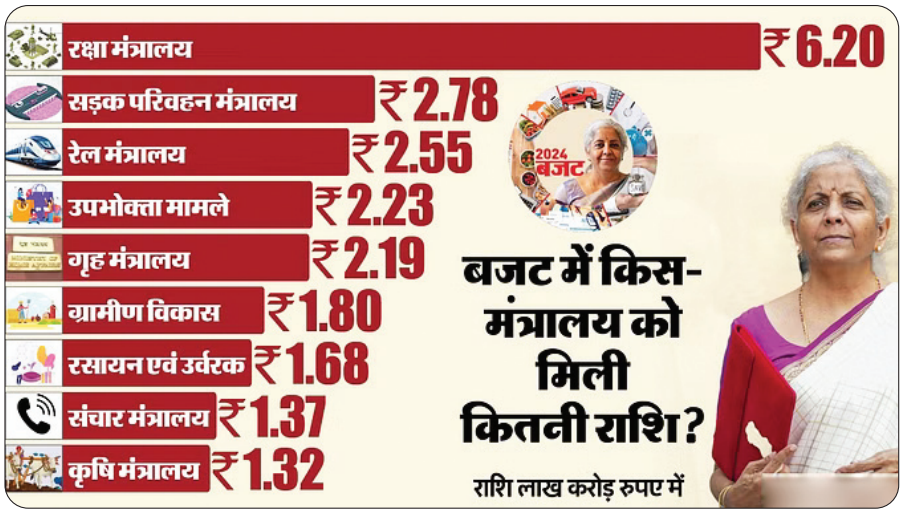

जाएगा। सराकर इंडस्ट्री के साथ मिलकर वर्किंग हॉस्टल भी बनाएगी।

पहली नौकरी पाने वाले जिन लोगों की सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी उन्हें EPFO में पहली बार रजिस्टर करने पर 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में दी जाएगी। इसके साथ, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। निर्मला सीतारमण ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रमों को संरेखित किया जाएगा। इसी तरह नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जो युवा किसी मौजूदा योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उन्हें घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा प्रमोटेड फंड से गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा दी जा सके। इससे हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलेगी। फरवरी 2024 में अंतरिम बजट आवंटन कुल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 4.6% था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सकल घरेलू उत्पाद के 6% की सिफारिश से कम है। इस बीच, स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए आवंटन को संशोधित अनुमानों से मामूली रूप से बढ़ाकर अंतरिम बजट में रिकॉर्ड 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकारी स्कूलों को आधुनिक स्कूलों में बदलने की पहल के चलते PM SHRI के लिए प्रावधान वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमानों से दोगुना से अधिक बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 में 6,050 करोड़ रुपए कर दिया गया।

आवास से लेकर फ्री बिजली और स्वास्थ्य तक, लोगों को ऐसे मिलेगा इस बजट से फायदा-समग्र शिक्षा अभियान के लिए बजट 4,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 37,500 करोड़ हो गया। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमान से लगभग 60% घटाकर 2,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए अनुदान भी घटकर 10,324 करोड़ रुपए रह गया। सीतारमण के अनुसार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 से अब तक 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। सरकार से शिक्षा को और अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए शैक्षणिक वस्तुओं और सेवाओं पर मौजूदा 18% GST को घटाकर 5% करने का आग्रह भी किया है।

केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण : सीएम साय

रायपुर **(प्रदेश रुचि)**। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दूरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी जी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी : केदार कश्यप

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर वनमंत्री केदार कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट देश के विकास को गति देने वाला बजट है। इस

बजट में कृषि योजनाओं को और अधिक गति देने जो प्रावधान किए गए हैं उनका लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा । उक्त बातें प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने अपनी बजट प्रतिक्रिया में कही हैं। वनमंत्री कश्यप ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की वित्त मंत्री की दूरगामी सोच ने बजट को सर्वस्पर्शी बनाया है। यह हम सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है ।इस बजट में कृषि ,शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर अधिक फोकस किया गया है । ग्रामीण विकास के लिए अधिक बजट का प्रावधान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास सराहनीय है। वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के प्रधानमंत्री का फैसला युवाओं को रोजगार देने को दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा । उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 3 करोड़ और मकान बनाए जाने को बजट में शामिल करना गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित होगा ।

केंद्र के बजट में विकसित भारत 2047 की झलक : रामविचार नेताम

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 की झलक है। यह बजट गरीबों,

युवाओं, किसानों और महिलाओं की सशक्तिकरण पर केंद्रित है। नेताम ने विकसित भारत की लक्ष्य को लेकर पेश की गई बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबको अवसर के सिद्धांत पर आधारित इस बजट में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। नेताम ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान किया है इस फंड से कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों से जुड़े उत्पादन संगठनों, कोऑपरेटिव और स्टार्टप को बढ़ावा देने की बात कही गई है। जो एक सराहनीय पहल है। मंत्री नेताम ने कहा कि बजट में जनजातियों के विकास के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सरकार जनजातीय

नौकरी, निवेश, किसान, युवा महिला कल्याण को समर्पित बजट : अरुण साव

केंद्रीय बजट प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बजट को नई नौकरियों का सृजन करने वाला, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, किसान युवा और महिला कल्याण के क्षेत्र

में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है। एक तरफ सरकार ने बजट के आकार में ऐतिहासिक वृद्धि की है, सरकार द्वारा किए जानेवाले खर्च को बढ़ाकर लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया है। वहीं आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रावधान करके देश में परिवहन की लागत को कम करने के ठोस उपाय किए है। निवेश संभावनाओं को नए पंख दे दिए गए है। साव ने बताया कि सरकार के लगातार अपने बजट के आकर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है ये निर्णय देश के आर्थिक विकास को नई संभावनाएं दे रहा है। ये बजट देश के नागरिकों और देश के सुनहरे भविष्य का बजट है। साव ने कहा मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने बजट में सारी आर्थिक चुनौतियों को चुनौती देते हुए देश के नागरिकों को फायदा देने के साथ देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के प्रावधान करने में सफलता हासिल की है।

अनुपूरक बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा : लक्ष्मी राजवाड़े

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 23 जुलाई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का विधानसभा में प्रथम अनुपूरक ध्वनिमत से पारित

हुआ। सदन में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत किए गए 7 हजार 329 करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट में महतारी वंदन योजना, पीएम जनमन योजना, के साथ खेल सुविधाओं, आंगनबाड़ी भवन, सहित अनेक योजनाओं एवं विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखे गए हैं। साय सरकार ने यह अनूपूरक बजट विकसित भारत और छत्तीसगढ़ विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बजट सत्र पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि यह बजट महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के लिए 4 हजार 900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस बजट में गरीब, महिला, मध्यमवर्गीय, छोटे व्यापारियों सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास हो सके।

अमृतकाल के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाला बजट : बृजमोहन

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह बजट, सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा, गरीब, महिला, किसान, सभी वर्गों की चिंता की गई है। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने के लिए 2 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, 1 साल तक उन्हें 5 हजार रुपए प्रति माह केन्द्र सरकार की ओर से मिलेगा। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास केलिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1 लाख रुपये से कम सैलरी होने वाले प्रवेशकों को ईपीएफओ में रजिस्टर होने पर केंद्र सरकार से 15,000 रुपये मिलेंगे। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ होगा। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार आरंभ करने के लिए 7.50 लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं 10 लाख तक के शिक्षा ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर की छूट के आधार पर दिया जाएगा। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को आगामी 5 साल तक अनाज देने के वादे को निभाया

देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट : अमर अग्रवाल

पूर्व वित्त मंत्री एवं विधायक अमर अग्रवाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में सर्वांगीण, सर्वव्यापी तथा सर्व-समावेशी विकास के साथ वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' की परिकल्पना की गई है।बजट में चार वर्ग गरीब, महिला, युवा और किसान का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा इस बजट में विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग पर फोकस किया गया है। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं.5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ होगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए उत्पादकता और अनुकूलनीयता 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर नए घर बनाये जाएंगे।मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई है।बजट में एम एस एम ई MSME के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान किया गया है।एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू होगी। उन्होंने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुश्किल दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.

ग्रामीण जीवन के उत्थान में मील पत्थर साबित होगा यह बजट : विजय शर्मा

केंद्रीय बजट 2024-25 पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसे विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याणकारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा होम अफेयर्स के लिए 150983 करोड रुपए का प्रावधान, मनरेगा का बजट 60000 करोड़ से बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपये करना, 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास हेतु, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ नए घरों का निर्माण, पीएमजीएसवाई चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क ग्रामीण जीवन के उत्थान में सहायक होगा। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा।

बजट से सभी वर्ग छले गए : सुशील

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार के बजट से गरीब, युवा किसान, मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा, महिला सभी छले गये है, इस बजट में रोजगार के लिये, कृषि के लिये, लघु उद्योगों के लिये कुछ भी नही है। बजट में सुदृढ़ भारत का रोड मैप कहीं भी नहीं दिख रहा है बजट में महंगाई कम करने के बारे में वित्तमंत्री ने कोई प्रावधान नही किया है। गरीब, मध्यम वर्ग को महंगाई से राहत नही मिला है उल्टे इस बजट में निम्न मध्यम वर्ग को भी आयकर के दायरे में ला दिया गया है। बजट देने के लिये जनता से वसूलने के लिये बनाया गया है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस सरकार में रोजगार है नहीं और ईपीएफओ के प्रोत्साहन का झांसा दिया जा रहा है, वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है 14 लाख करोड़ का नया कर्ज देश को गर्त में डूबने वाला है महंगाई में राहत नहीं, गैस सब्सिडी, डीजल में 10 गुना बढ़ाए गए सेंट्रल एक्साइज में रियायत का कोई जिक्र नहीं छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है।

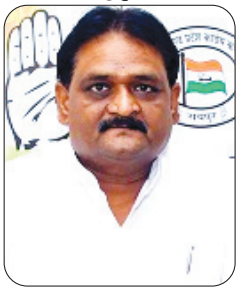

बजट को लेकर मिली अलग अलग प्रतिक्रिया

बालोद (प्रदेश रुचि)

23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 पर भाजपा और कांग्रेस नेताओ ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए इस बजट को लेकर भाजपाइयों ने इसे देश को उच्च शिखर तक पहुंचने वाला बजट बताया तो वही कांग्रेसियों ने इस बजट को निराशाजनक बताते हुए आम जनता के साथ धोखा वाला बजट बताए। वही बजट को लेकर बालोद के भाजपा जिला अध्यक्ष पवन साहू ने कहा है कि केंद्र के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान, युवा पर बजट में फोकस किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया गया है। जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। उन्होंने कहा कि 4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा, उनका कौशल बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए मकानों का ऐलान ग्रामीण विकास के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष **कृष्ण कांत पवार** ने बजट को विकासोन्मुखी, समावेशी और जनकल्याण-कारी बताया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रावधानों की सराहना की और इसे देश सहित प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।

यशवंत जैन ने गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि से ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा होम अफेयर्स के लिए 150983 करोड रुपए का प्रावधान , मनरेगा का बजट 60000 करोड़ से बढ़कर 86 हजार करोड़ रुपये करना, 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास हेतु, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ नए घरों का निर्माण, पीएम-जीएसवाई चरण IV 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क ग्रामीण जीवन के उत्थान में सहायक होगा।

पूर्व नपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा ने कहा तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों को भी सराहा गया है,उन्होंने कहा कि नए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना से युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 5 साल में 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, स्किल इंडिया के तहत युवाओं को प्रशिक्षित और पुनर्प्रशिक्षित करने के कदम देश की तकनीकी दक्षता को बढ़ाएंगे।।

पूर्व नपाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदम देश की तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देंगे। शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए गए कोष से नई खोजों और आविष्कारों को बल मिलेगा।

पूर्व विधायक प्रीतम साहू ने कहा - वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में ऐलान किया की माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार एनपीएस वात्सल्य लॉन्च करेगी । इनकम टैक्स आसान होगा टीडीएस पर भी बड़ा ऐलान की बात करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया की इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा, टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।

जिला महामंत्री चेमन देशमुख ने कहा कि मोबाइल फोन सस्ते होंगे बजट में बड़ा ऐलान किया गया है, मोबाइल फोन चार्जर सस्ते होंगे इसके अलावा बिजली के तार एक्स-रे मशीन सस्ती होगी कैंसर की तीन दवाइयां से कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई चमड़े के जूते चप्पल पर्स सस्ते होंगे इसके साथ ही सोना चांदी भी सस्ता होगा इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती होगी कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा कि सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6: 5% प्रतिशत की जाएगी।

पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू ने कहा नवाचार अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, बुनियादी अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक लाख करोड रुपए का वित्त पोषण पूल भी बनाया जाएगा।

जिला महामंत्री राकेश छोटू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार 109 उच्च पैदावार वाली फसलों पर फोकस करते हुए दलहन, तिलहन और सब्जियों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी ध्यान दे रही है और 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ ही सिंचाई के लिए साढ़े 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि क्षेत्र के समुन्नत होने का स्वर्णिम अवसर है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5

साल जारी रखने की घोषणा भी स्वागत योग्य है।

भाजपा अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष अकबर तिगाला ने कहा कि टीडीएस के

नियमों को सरल करने, आयकर में टैक्स स्लैब में किए गए बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन में की गई बढ़ोत्तरी का स्वागत किया और कहा कि अमृतकाल का यह बजट हर मायने में संतुलित और महत्वपूर्ण है। रोजगार के अवसरों की संभावनाओं का द्वार खोलते हुए केंद्र सरकार ने रोजगार और कौशल उन्नयन के लिए 1 लाख करोड़ और नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने का संकल्प व्यक्त किया है। इसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख नौकरियाँ देने का इरादा बजट में व्यक्त करके युवाओं के विकास और आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त किया है।

जिला पंचायत सदस्य संध्या भारद्वाज ने कहा कि केंद्र राजग सरकार ने अपने प्रस्तुत बजट में महिलाओं के उत्थान के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करके नारी उत्थान की अपनी प्रतिबद्धता को साकार किया है। बजट में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने का संकल्प व्यक्त कर देश के 63 हजार ग्रामों के 5 करोड आदिवासियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य व्यक्त किया है।

जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र चंद्राकर ने कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का

पहला बजट पेश हो रहा है वित्त मंत्री ने इस दौरान कई राहत का ऐलान किया वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब युवा महिला किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। भारत की जनता ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए दोबारा चुना है

संध्या अजेंद्र साहू ने कहा इस बार के बजट में कृषि, रोजगार, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा के अलावा गरीब, महिला, किसान युवा पर बजट में फोकस किया गया है। यह बजट देश सहित प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सभी क्षेत्रों में सुधार और प्रगति को बढ़ावा देगा।

वही बजट को लेकर बालोद जिले के अलावा प्रदेश के अलग अलग जगहों से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस बजट को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार का बजट देश की जनता को निराश करने वाला है। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था का बर्बाद करने वाला है। बजट में निम्न, मध्यम वर्ग पर भार डाला गया है। पुराने टैक्स रिजिम में पिछले 10 वर्षों से आयकर छुट की सीमा वही की वही है, इस बार भी नहीं बढ़ा। 80 सी और 80 डी की लिमिट भी यथावत है। मकान के लिए ऋण की छुट भी नहीं बढ़ी। यदि 50 हजार रू. भी महिना कमा रहे है तो 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। नये टैक्स स्लेब के अनुसार लगभग पूरे निम्न, मध्यम आय वर्ग से कर वसूला जायेगा।

मोदी का चुनाव में वादा 4 करोड़ मकान बनाने का था लेकिन बजट में सिर्फ 1 करोड़ मकान के लिये प्रावधान किया है। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है।

इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। जो 30 लाख नौकरियां केन्द्र सरकार के अधीन खाली है उनको भरने के बारे में बजट में कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन और छात्रों तथा मासिक पास धारकों के लिये छूट रेलवे में समाप्त की गयी थी इस बजट में उसको बहाल नहीं किया गया है। बजट से किसान और खेती की उपेक्षा की गयी है। लघु एवं कुटीर उद्योगो को बढ़ावा देने के लिये बजट में कुछ नहीं है।

अपनी दो बैसाखियों बिहार और आन्ध्रप्रदेश के लिये विशेष प्रावधान किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल राज्य की उपेक्षा की गयी है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा एक बार फिर से जाहिर हो गया है, कि भाजपा के लिये छत्तीसगढ़ का विकास कोई मायने नहीं रखता। चुनाव में डबल इंजन की सरकार के फायदे बता कर वोट लिया था। बजट में डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ से धोखा किया। रायपुर से राजनांदगांव होकर हैदराबाद एक्सप्रेस वे, जो 2022 में घोषित किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है इस बजट में कोई नया राजमार्ग छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि बजट से महिलाओं को हर बार की तरह इस बार भी बजट में निराशा हाथ लगी। महिलाओं को बजट से बहुत ही उम्मीद थी कि एक महिला वित्त मंत्री है जो महिलाओं की परेशानी को समझ कर बजट पेश करेगी लेकिन यह अनुमान हर बार की तरह इस बार भी गलत निकला। इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं। महिलाओं को लग रहा था कि खाने-पीने की वस्तुओं में पहली बार यदि कोई सरकार जीएसटी लगाया था तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो खाद्य पदार्थ पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाए थे जिसके कारण खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। महिलाओं के रसोई में संकट छाया हुआ है। आज गरीब के थाली से दाल गायब हो रही है। सब्जी गायब हो रहा है। आज भरपेट भोजन देने के लिए अपने परिवार के पालन पोषण के लिए महिलाओं की माथे पर चिंता की लकीरें छाई हुई है लेकिन इस बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। यह बजट सिर्फ दिखावे की बजट है।

नितिश और नायडू के धमकाने का दिखा असरःभूपेश बघेल

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को बजट प्रस्तुत किया गया। बजट को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, यह बजट कुर्सी बचाने वाला बजट है। नितीश और नायडू ने धमकाया है, उसका असर दिखा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार बचाने के लिए समझौता किया यह स्पष्ट दिख रहा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इतनी सीटें दी लेकिन दोनों राज्यों को कुछ नहीं मिला।

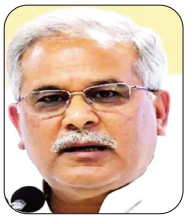

कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ बन गया था अपराध गढ़ : किरण देव

रायपुर (प्रदेश रुचि)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कानून-व्यवस्था और अपराध को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को मुद्दाविहीन कांग्रेस का राजनीतिक प्रदर्शन बताया है। देव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सशक्त नेतृत्व में भाजपा की प्रदेश सरकार में सबको न्याय मिलने की गारंटी है और सबको न्याय मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि सभी की मुकम्मल सुरक्षा का समुचित उपाय प्रदेश सरकार ने किया है, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में अपराधी बेलगाम थे और अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता था। कांग्रेस के राज में जो पीड़ित होते थे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। कांग्रेस शासनकाल में अंजाम दिए गए ऐसे तमाम अपराधों पर अब भाजपा सरकार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों को

सींखचों के पीछे डाल रही है। देव ने कहा कि इससे अधिक शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि कांग्रेस के शासन में कांग्रेस के ही विधायक तक तत्कालीन गृह मंत्री के सामने यह बोलते थे कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है और सब्जी वालों, टमाटर वालों से भी पैसे वसूली करती है। देव ने कहा कि आज कानून-व्यवस्था के नाम पर प्रलाप करते कांग्रेसी पहले यह बताएं भूपेश सरकार के समय आखिर हो क्या रहा था? प्रदेश में सरकार चल रही थी या माफिया गुंडाराज? एनएसयूआई के अध्यक्ष शराब दुकानों से अवैध वसूली कर रहे थे। कांग्रेस के लोग यह कतई न भूलें कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ अपराधियों का गढ़ बन गया था और अपराधी तमाम अपराध पुलिस की नाक के नीचे संगठित गिरोह बनाकर अपराध कर रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब भाजपा की सरकार है, जिसके शासन में अपराधियों को पकड़ा जाता है, हर अपराध की एफआईआर लिखी जाती है। यहाँ पर कोई अपराधी बच नहीं सकता। अपराधियों में खौफ कायम हो रहा है और कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ जो अपराध गढ़ बन गया था, उसे फिर से शांति का टापू बनाने के लिए भाजपा की प्रदेश सरकार संकल्पित है और उस दिशा में सुविचारित रणनीति बनाकर काम कर रही है। देव ने कहा कि दरअसल कानून-व्यवस्था तो कांग्रेस के लिए एक बहाना भर है। कांग्रेसी कानून-व्यवस्था का प्रलाप मचाकर खुद के मृत संगठन को जिंदा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता जनार्दन कांग्रेस के झूठ, झाँसों व प्रपंच की राजनीति से भलीभाँति वाकिफ हो चुकी है, पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनावों के नतीजे इस बात की तस्दीक़ कर रहे हैं।

देश में कैंसर रोकथाम की दिशा में तेजी से हो रहा काम...

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर पीएमओ ने दिया जवाब

रायपुर(प्रदेश रुचि)। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कैंसर के रोकथाम की दिशा में तेजी से काम कर रही है। देश में सभी उच्च मूल्य की कैंसर रोधी दवाओं के दामों में समूह समझौता के परिणाम-स्वरूप औसतन 82% फीसदी की कमी आई है। यह कहना है रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल का।

दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने देश में उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर केयर को लेकर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ जानकारी मांगी थी कि, जिसमे पूछा गया था कि, रोगियों को वहनीय लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली कैंसर-परिचयर्या सुनिश्चित करने, पिछले चार वर्षों के दौरान कैंसर-केयर के क्षेत्र में आरम्भ किए गए विशिष्ट अनुसंधान के परिणाम और राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की कैंसर-केयर में भूमिका, इसके केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों आदि की राज्य-वार सूची मांगी थी। जिसपर राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पैशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि, परमाणु ऊर्जा विभाग के तत्वावधान में एक सहायता प्राप्त संस्थान टाटा स्मारक केंद्र 60:40 अनुपात मॉडल पर काम करते हुए किफायती लागत पर उच्च गुणवत्ता की कैंसर देखभाल प्रदान कर रहा है। जिसके तहत 60% रोगी अत्यधिक आर्थिक सहायता पर इलाज या लगभग निःशुल्क इलाज प्राप्त कर रहे हैं और 40 फीसदी काफी रियायती दरों पर इलाज करा रहे हैं। साथ ही कैंसर प्रबंधन के लिए स्रोत आधारित दिशानिर्देशों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है जिससे लाभार्थियों के लिए देखभाल सुविधा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। जितेंद्र सिंह ने पिछले चार वर्षों में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में टीएमसी द्वारा शुरू किए गए विशिष्ट अनुसंधान परिणाम का विवरण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि, अब तक 400 से अधिक ऑन्कोलॉजिस्ट प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। टीएमसी द्वारा किए गए एक प्रमुख यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (आरसीटी) से इलाज की दरों में 26% की वृद्धि हुई। जिससे प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों की जान बचाने की आशा है। बृजमोहन अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए सिंह ने बताया कि, राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड अब 340 कैंसर केंद्रों, अनुसंधान संस्थानों, रोगी पक्षपोषण समूहों, परोपकारी संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के एक बड़ा नेटवर्क में विकसित हो गया है। जो एनसीजी प्रतिवर्ष 8.5 लाख से ज्यादा नए रोगियों का उपचार करता है, जो भारत के कुल कैंसर रोगियों का लगभग 60 प्रतिशत है। भारत में कैंसर देखभाल के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए, यह कैंसर की रोकथाम में एक मजबूत, एकीकृत और शक्तिशाली साधन है।

जनता में विश्वास बहाली बड़ी चुनौती

मोदी की गारंटी पूरी कर जीता भरोसा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर(प्रदेश रुचि) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ सरकार के छह माह पूरे होने पर नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित सुशासन संवाद कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियां व राज्य में सुशासन की दिशा में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होने जनता के सवालों का भी बेबाकी के साथ जवाब दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने संबोधित करते हुये कहा शपथ ग्रहण के पश्चात हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता के भरोसे पर खरा उतरना था। मोदी जी ने जो प्रदेश की आम जनता को गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करना था। लेकिन हमने 7 महीने के भीतर ही अधिकांश गारंटियों को पूरा कर जनता का भरोसा पुनः अर्जित कर लिया है। उन्होने कहा छत्तीसगढ़ में जनता का काम साएँ-साएँ हो रहा है, जिससे कमीशनखोरी करने वालों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ₹हमारी सरकार की नियत और नीति दोनों सही हैं। उन्होने नक्सलवाद के विरुद्ध किए गए कार्यों पर विशेष जोर देते हुये कहा ₹हमारी सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। हमने सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं और इन इलाकों में विकास कार्यों को तेज किया है। इससे न केवल सुरक्षा बल्कि विकास की दिशा में भी हमें बड़ी सफलता मिली है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, ₹हमने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि जनता को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी और प्रभावी तरीके से मिल सके।₹ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुये कहा कि हमने सरकार बनते ही मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया। किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस दिया। वादे के अनुरूप 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी शुरू की। राज्य की महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, ₹हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा सपनों का छत्तीसगढ़ तैयार हो रहा है। राज्य के विकास के लिए हमने कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं और जनता को उनकी आवश्यकता की सभी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ को अयोध्या तक मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात

रायपुर(प्रदेश रुचि). छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। बैठक में राज्य में चल रही सड़क परियोजनाओं और आदिवासी क्षेत्रों में व अयोध्या तक सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क परिवहन को और अधिक सुलभ व सुविधाजनक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। जिस पर केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, श्री राहुल भगत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति एवं सुदूर आदिवासी वनांचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने रायगढ़-धरमजयगढ़-मैनपाट-अंबिकापुर-उत्तरप्रदेश सीमा तक कुल 282 किमी तक के मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की है। श्री साय ने बताया यह मार्ग प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरता है एवं धार्मिक नगरी अयोध्या से छत्तीसगढ़ राज्य को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है।

मुख्यमंत्री ने कवर्धा-राजनांदगांव-भानुप्रतापपुर-अंतागढ़-नारायणपुर-गीदम-दंतेवाड़ा-सुकमा मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया यह कुल 482 किमी लंबा राज्य के कुल 6 राष्ट्रीय राजमार्गों एवं 5 जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से बस्तर का नक्सल प्रभावित क्षेत्र मुख्यमार्ग से जुड़ेगा एवं नक्सल गतिविधियों में कमी आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा रायपुर शहर से तीन राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एनएच 130बी से 53 को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा यह मार्ग एनएच घोषित होने से रायपुर शहर का रिंग रोड पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा।

इसके अलावा उन्होंने रतनपुर-लोरमी-मुंगेली-नांदघाट-भाटापारा-बलौदाबाजार मार्ग, केंवची-पेंड्रारोड-पसान-कटघोरा मार्ग, मुंगेली-नवागढ़-बेमेतरा-धमधा-दुर्ग-झलमला मार्ग, राजनांदगाँव-मोहला-मानपुर मार्ग, पंडरिया-बजाग-गाड़ासरई मार्ग को भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने रखा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में कटघोरा से अंबिकापुर तक फोर लेन चौड़ीकरण करने तथा एनएच क्रमांक 53 पर टाटीबंध से तेलीबांधा तक सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सरोना चौक, उद्योग भवन, और तेलीबांधा चौक पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण की आवश्यकता बताई है इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के वार्षिक योजना 2024-25 में एनएच 30 धमतरी से जगदलपुर व एनएच 130बी में रायपुर-बलौदाबाजार-सारंगढ़ मार्ग फोर लेन करने का प्रस्ताव रखा है।

साय ने ओम बिड़ला से की मुलाक़ात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला से मुलाक़ात की। संसद भवन में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य और केंद्र के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विशेष रूप से राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं और आगामी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

छत्तीसगढ़ को मिले पांच राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर(प्रदेश रुचि).भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज नई दिल्ली में प्रदान किए गए ह्यस्पार्कह्ल पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ का दबदबा रहा। राज्य को इसमें विभिन्न श्रेणियों में पांच पुरस्कार मिले। प्रदेश के तीन शहरों को अपनी-अपनी श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार, एक नगरीय निकाय को द्वितीय पुरस्कार और राज्य स्तरीय पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित समारोह में ये पुरस्कार वितरित किए। छत्तीसगढ़ से गए 20 अधिकारियों और लाभार्थियों की टीम ने अपने-अपने निकायों की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किए।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे-एनयूएलएम) में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित ह्यस्पार्क 2023-24ह्ल पुरस्कारों के अंतर्गत दस लाख तक जनसंख्या श्रेणी में बिलासपुर नगर निगम को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं तीन लाख तक जनसंख्या श्रेणी में रायगढ़ नगर निगम को और एक लाख तक जनसंख्या श्रेणी में भाटापारा नगर पालिका को पूरे देश में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। चांपा नगर पालिका को 50 हजार तक जनसंख्या श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और चारों नगरीय निकायों की टीम के साथ ही प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार राज्य के लिए सम्मान का विषय है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार और कौशल विकास के साथ ही शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन महिलाओं एवं युवाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध मिशन है। छत्तीसगढ़ इस मिशन में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में अच्छे कार्यों को रेखांकित करने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के नामांकित लाभार्थी जशपुर नगर पालिका के श्री सुमित किस्कु और लोरमी नगर पंचायत के श्री कुशाल राम साहू भी शामिल हुए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभार्थी के रूप में नामांकित जगदलपुर नगर निगम की हैप्पी महिला स्वसहायता समूह की श्रीमती मृदुला जैन, भिलाई नगर निगम की राधा रानी स्वसहायता समूह की श्रीमती चित्ररेखा साहू, सिटी मिशन प्रबंधक सुश्री एकता शर्मा और श्री संत कुमार महतो ने भी छत्तीसगढ़ की ओर से समारोह में सहभागिता दी।

राज्य की ओर से इन्होंने ग्रहण किए पुरस्कार-नई दिल्ली के इंडिया हैबिटॉट सेंटर में आयोजित पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ को मिला तृतीय पुरस्कार सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील अग्रहरि, राज्य मिशन प्रबंधक श्री विवेक शुक्ला और श्री प्रशांत अमोली ने ग्रहण किया। बिलासपुर नगम निगम के आयुक्त श्री अमित कुमार, रायगढ़ नगर निगम के आयुक्त श्री सुनील चंद्रवशी, सिटी मिशन प्रबंधक श्री केदार पटेल और श्री शुभम शर्मा, भाटापारा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री लाल अजय बहादुर सिंह और सिटी मिशन प्रबंधक श्री नीरज साहू तथा चांपा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी और श्री भोला सिंह ठाकुर ने अपने-अपने निकायों की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया।

केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन, संयुक्त सचिव तथा एनयूएलएम एवं पीएम स्वनिधि के प्रबंध निदेशक श्री राहुल कपूर, पीएम स्वनिधि की संचालक श्रीमती शालिनी पाण्डेय और एनयूएलएम के संचालक श्री सुनील कुमार यादव भी पुरस्कार समारोह में मौजूद थे।

अटल जी ने पृथक राज्य बनाकर दिया, इसे संवारने की जिम्मेदारी हमारी : मुख्यमंत्री

रायपुर (प्रदेश रुचि)

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डॉ. खूबचंद बघेल व्यावसायिक परिसर, फूल चौक में आयोजित डॉ. खूबचंद बघेल की 124वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डॉ. खूबचंद बघेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री टंकराम वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने डॉ. खूबचंद बघेल का पुण्य स्मरण करते हुए कहा कि वे छत्तीसगढ़ के स्वप्नद्दष्टा थे। एक अच्छे डॉक्टर और साहित्यकार के रूप में उनकी अलग पहचान थी। मुख्यमंत्री श्री साय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों का सपना पूरा किया। हम सभी अटल जी के आभारी हैं। अब इस राज्य को संवारने की जिम्मेदारी हम सभी की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से सरकार के मुखिया का दायित्व मुझे मिला है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 7 माह पूरे किए हैं और सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का काम किया। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। 13 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस का अंतरण, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को हर महीने एक-एक हजार रुपए सालाना 12 हजार रूपए की सहायता राशि के साथ ही तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए संग्रहण दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए प्रति मानक बोरा करने जैसे कई अहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने जिस छत्तीसगढ़ का सपना देखा है, उसे आकार देने के लिए हम सभी कार्य कर रहे हैं। हमारे पास खनिज संपदा भरपूर मात्रा में है। हमारे पास कोयला, आयरन, बॉक्साइट, गोल्ड, डायमंड जैसे खनिज उपलब्ध हैं। मिनरल्स के क्षेत्र में भी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत समृद्ध है। तरह-तरह के वनोपज हमारे छत्तीसगढ़ की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके वैल्यू एडिशन से हम वनवासी भाइयों-बहनों के जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बना रहे हैं। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने उपस्थित लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि हम समाज और प्रदेश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएं। डॉ. खूबचंद बघेल ने समाज में भेदभाव को मिटाने के लिए और गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के कायर्कारी अध्यक्ष श्री के के नायक ने डॉ. खूबचंद बघेल के प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और सामाजिक उत्थान के लिए उनके योगदानों के बारे में विस्तार से बताया।

गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार सख्त

रायपुर (प्रदेश रुचि). छत्तीसगढ़ में गौ वंश के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती दिखाई है. डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नया आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर परिवहन अवैध होगी. गैर जमानती अपराध माना जाएगा. अवैध परिवहन पाए जाने पर सात साल तक की सजा और पचास हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. जिस रूट पर अवैध परिवहन पाया जाता है वहां के एसपी और थाना प्रभारी का सीआर भी खराब होगा. आदेश में कहा गया है कि अवैध परिवहन करने वालों पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ की जिम्मेदारी होगी. परिवहन के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी में फलैक्स लगाने की अनिवायर्ता होगी. अवैध परिवहन में इस्तेमाल गाड़ी राजसात की जाएगी. गाड़ी मालिकों पर भी कारवाई की जाएगी. गौ वंश के अवैध परिवहन को रोकने जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति होगी. ये नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे. अवैध परिवहन के पुराने प्रकरणों को जिलेवार एकत्रित किया जाएगा. आदतन अपराधियों को ट्रैक किया जाएगा. उन रास्तों पर भी निगरानी कड़ी होगी, जहां से अवैध परिवहन किया जाता रहा है.यदि नियम विरूद्ध परिवहन होना पाया जाता है तो जहां से परिवहन शुरू हुआ और जहां वाहन जब्त किया गया, इस बीच के सभी पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारियों के सर्विस बुक में नकारात्मक टीप दर्ज की जाएगी. अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कारवाई होगी.

ये हैं प्रमुख प्रावधान

- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 अनुसार पशुओं को मारने, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, अत्यधिक बोझ लादेगा या किसी यान में ऐसे रीति से ले जाएगा, जिससे उसे यातना पहुंचती है या उसे परिरूद्ध करेगा, पर्याप्त खाना, जल या आश्रय नहीं देगा, उनके विरुद्ध दांडिक कायर्वाही किए जाने का प्रावधान किया गया है।
- गौवंश एवं दुधारू पशुओं की तस्करी एवं वध की घटनाओं के रोकथाम के लिए आसूचना तंत्र विकसित किया जाएगा।
- गौवंश का वध व वध किए जाने का प्रयास किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज कर अभियुक्तों की पहचान स्थापित करते हुए कायर्वाही की जाएगी।
- गौवंश एवं दुधारू पशुओं को अवैध परिवहन (तस्करी) के दौरान जब्त करने पर नियमानुसार संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए गौशाला कांजी हाउस या संबंधित संस्था को सुपुदर्गी में दिया जाएगा।
- पशु वध शालाओं के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विधिसम्मत कायर्वाही की जाएगी।
- गौवंश का परिवहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में अनुज्ञापत्र के बिना परिवहन न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- अनुज्ञापत्र धारक वाहनों में मवेशी के परिवहन करते समय पृथक से ऐसे वाहनों पर फ्लैक्स/बैनर लगाकर चिन्हाकिंत किया जाएगा कि ऐसे वाहन में गौवंश का परिवहन किया जा रहा है।
- अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात किया जाएगा एवं वाहन मालिक पर भी आपराधिक दाण्डिक कायर्वाही किया जाएगा
- प्रकरण में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी कायर्वाही सुनिश्चित की जाएगी।
- आरोपी, संदिग्ध, गवाह व मुखबीर से सघन पूछताछ करते हुए सूचना एकत्रित किया जाएगा।
- विगत वर्षों में हुई घटनाओं की जानकारी संकलित व सूचीबद्ध करते हुए तस्करी के रूट, संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित करते हुए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी।
- जिला/थाना स्तर पर गौवध तथा गौवंश की तस्करी की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर इनके विरूद्ध वैधानिक कायर्वाही की जाएगी।
- प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में विशेष रूप से अवैध परिवहन (तस्करी) रोकने संवेदनशील क्षेत्रों में स्थैतिक सविर्लेंस पाइंट स्थापित की जाएगी।
- तस्करी में प्रयोग होने वाले संभावित मार्गों पर निरंतर पेट्रोलिंग की जाएगी।
- अभियुक्तों द्वारा अवैध तस्करी से अर्जित सम्पत्ति को चिन्हित करते हुए नियमानुसार जब्ती/कुर्की की कारवाई की जाएगी।
- विगत वर्षों की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की सूची तैयार कर आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाएगी।
- अपराध में संलिप्त सह-अभियुक्तों व सहयोगियों को चिहिन्त कर उन पर सतत निगरानी रखी जाएगी।
- उक्त प्रकरणों में अपराध विवेचना के साथ वित्तीय जांच एवं मनीट्रेल का भी पता लगाया जाएगा।
- उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए अन्य विधि प्रवर्तक एजेंसी व राज्यों के साथ भी जानकारी साझा की जाएगी।
- जिला स्तर पर गौवंश के वध तथा गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) से संबंधित समस्त लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार कर इनका समुचित पयर्वेक्षण/मानिटरिंग करते हुए शीघ्र कायर्वाही पूर्ण कराकर निराकरण किया जाए।
- दोषमुक्ति प्रकरणों की समीक्षा किया जाकर विवेचना की कमियों की पूर्ति के लिए आवश्यक कायर्वाही की जाए।
- न्यायालय में विचाराधीन मामलों की अभियोजन में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, जिससे अभियुक्तों की जमानत का लाभ न मिल सके तथा अभियुक्त को अभियोजित किया जा सके।
- जिला स्तर पर एक राजपत्रित अधिकारी को उक्त घटनाओं की रोकथाम व पयर्वेक्षण करने नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. इसकी जानकारी सभी थानों/जिला स्तर/सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उक्त घटनाओं के संबंध में जानकारी नोडल अधिकारी को प्रदान की जा सके। यदि किसी पुलिस अधिकारी/कमर्चारी की गौवंश के वध, गौवंश व दुधारू पशुओं की तस्करी (अवैध परिवहन) की कायर्वाही में किसी प्रकार की शिथिलता व संलिप्तता पायी जाती है तो उनके विरूद्ध कठोर कारवाई की जाएगी.

अपने काम को पूरी ईमानदारी और दक्षता से करना ही देशसेवा: मुख्यमंत्री साय

रायपुर (प्रदेश रुचि)

आप जिस रूप में भी देश की सेवा करना चाह रहे हैं, उस रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर बन मरीजों की सेवा कर देश की सेवा कर सकते हैं, जनप्र-तिनिधि बनकर जनता की समस्याएं दूरक र लोगों की मदद कर सकते हैं। अपने काम को बेहतर तरीके से और पूरी ईमानदारी से करना ही, आज के समय में सच्ची देश सेवा है। यह बात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा परिसर भ्रमण के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल तुलसी, रायपुर से आए बच्चों के प्रश्नों के उत्तर में कही। इस दौरान उपमु-ख्यमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय से बच्चों ने सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल-जबाव, विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा की कार्यवाही के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि सबसे पहले प्रश्नकाल होता है और इसके पश्चात सदस्य यदि किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। इसी तरह से उन्होंने शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित प्रश्न, अन्य प्रस्ताव, बजट के ऊपर एवं विधानसभा में होने वाली अन्य चर्चाओं एवं विधानसभा संचालन और गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र की समस्याएं दूर करने के लिए विधायकों के पास विधायक निधि होती है। इसके अलावा विभागीय बजट से भी कार्य स्वीकृत किए जाते है। विधायकों को मतदाता चुनकर भेजते हैं औ रक्षेत्र का विकास उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो लगातार सवाल करते है। दो विभागों के बीच विवाद की स्थिति को लेकर बच्चों की जिज्ञासा दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि नीति और नियत साफ है तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है। मुख्यमंत्री साय के लंबे संसदीय अनुभव से बच्चों को बहुत सारी जानकारियां मिली और उन्होंने मुख्यमंत्री को उत्सुकता के साथ सुना।मुख्यमंत्री साय ने बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि आप सभी निष्ठा से परिश्रम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। निजी स्वार्थ को छोड़कर हमें देशहित के लिए हमेशा समर्पित होकर कार्य करना होगा। जिस भी रूप में आप देशसेवा करना चाहते हैं, उसे तय कर इस दिशा में प्रयास करते रहें। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 साल की उम्र में मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो चुका था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच पाउंगा। मेरी इच्छा उन्नत किसान बनने की थी। लेकिन इस सफर में जो जिम्मेदारियां मुझे मिली, मैं उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहा। इ

स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री से पूछे विधानसभा संचालन को लेकर प्रश्न

सभी स्कूलों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की करेंगे पदस्थापना

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों और विद्यार्थियों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर है। उन्होंने बताया कि देश में 26 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक हैं जबकि प्रदेश में 21 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। शिक्षकों की पदस्थापना में अब तक कुछ अव्यवस्थाएं थी। जिसके कारण शिक्षकों की कमी परिलक्षित हो रही थी। इन कारणों से सर्वप्रथम युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता होगी। कुछ स्कूलों में जहां विषय संकाय है वहां शिक्षक नहीं है जहां विषय संकाय नहीं है वहां शिक्षक हैं। कुछ स्थानों पर राज्य के अनुपात से भी बहुत कम विद्यार्थियों पर शिक्षक है। कुछ स्थानों पर तो 4-5 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। युक्तियुक्त-करण की प्रक्रिया हेतु ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन किया जा रहा है और शीघ्र ही सभी स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना कर दी जाएगी। इससे सभी स्कूलों में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे और शिक्षा का स्तर और भी अच्छा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिक्षकों की व्यवस्था के साथ ही अधोसंरचना विकास पर भी हम काम कर रहे हैं।

ग्रीन स्टील से शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य के साथ ही खुलेंगे आर्थिक संभावनाओं के भी द्वार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सीआईआई द्वारा आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में हुए शामिल

रायपुर (प्रदेश रुचि)

क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया ग्रीन स्टील की ओर रुख कर रही है। स्टील के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक होने के नाते ग्रीन स्टील छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी, अपितु इस क्षेत्र में नवीन पहल कर हम बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की संभावनाओं का द्वार खोल सकते हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मेफेयर लेक रिसार्ट में आयोजित ग्रीन स्टील समिट 2024 में शामिल होने के अवसर पर कही। इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया है। समिट में देश भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारी उपस्थित थे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में सीआईआई को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश भारत का सबसे प्रमुख स्टील निर्माता है। हमारे यहां सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई स्टील प्लांट और नगरनार स्टील प्लांट जैसी बड़ी इकाईयां तो संचालित है ही, इसके साथ-साथ निजी क्षेत्र के अनेक छोटे-बड़े इस्पात संयंत्र संचालित हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है और छत्तीसगढ़ में लोहे के विशाल भंडार हैं, जिनमें बैलाडीला, रावघाट और दल्लीराजहरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग 20 प्रतिशत तक का योगदान है और राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योगों की भागीदारी 53.50 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इस्पात उद्योग से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के वैश्विक चिंताओं पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने का दृष्टिकोण सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की सराहना की और राज्य में सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों का उल्लेख किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि सीआईआई का यह समिट भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आज हम इस समिट में ग्रीन स्टील जैसे रोचक विषय पर बात कर रहे हैं। इस शब्द में खूबसूरती तो है ही, साथ ही साथ जिम्मेदारी भी है। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों से ग्रीन स्टील उत्पादन की नई तकनीक को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि हमारी एकजुटता से हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करते हुए मिलजुलकर विकास करेंगे।

छत्तीसगढ़ में भी अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण, सीएम साय ने की घोषणा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम साय ने ऐलान किया है कि, छत्तीसगढ़ सरकार सेवा के पश्चात् अग्निविरों को नौकरी में प्राथमिकता देगी। छत्तीसगढ़ के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के पश्चात वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। सीएम साय ने कहा कि, सरकार पुलिस में आरक्षक भर्ती, वनरक्षक, जेल प्रहरी आदि के पदों पर अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि, सरकार इसके लिए जल्द दिशा निर्देश जारी करेगी।

विधायकों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में लगाए पौधे

रायपुर (प्रदेश रुचि)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के आवासीय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी मां के सम्मान में वहां बेल का पौधा लगाया। विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सीताफल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने हनुमान फल और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नीम के पौधे का रोपण किया। विधानसभा आवासीय परिसर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने रामफल, वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने महुआ, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आंवला, श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हर्रा, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लक्ष्मण फल, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बेल तथा राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने पीपल का पौधा लगाया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायकों और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी मां की स्मृति और सम्मान में पौधे लगाए। कार्यक्रम में आज विभिन्न प्रजाति के सौ से अधिक पौधे लगाए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विधानसभा के आवासीय परिसर में 50 एकड़ क्षेत्र में इकोलॉजिकल पार्क (Ecological Park) विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यहां 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

नगरवासियों के सपनों के अनुरुप राजनांदगांव शहर का होगा विकास : डॉ. रमन सिंह

राजनांदगांव (प्रदेश रुचि)

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में शहर के विकास के लिए 13 करोड़ 81 लाख रूपए के लागत के 96 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव, सांसद श्री संतोष पाण्डेय, महापौर श्रीमती हेमा देशमुख विशेष रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव की जागरूकता पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पूरे

छत्तीसगढ़ में 7 माह के भीतर विकास का एक अद्भूत वातावरण निर्मित हुआ है। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों की शुरूआत हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे, उन सभी वादों को 7 माह से कम समय में पूरा किया गया है। सरकार ने 21 क्विंटल धान खरीदी, दो साल का बोनस, 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना, 45 सौ से बढ़ाकर 55 सौ रूपए तेन्दूपत्ता खरीदी सहित कई घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव ने उनका परिचय विधायक के नाते कराया है और पहचान बनाने वाला राजनांदगांव है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में छोटे-बड़े कई विकास मूलक कार्य करने में सफल रहे। मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सड़कों का निर्माण कार्य, फ्लाई ओवर, दिग्विजय स्टेडियम, शिवनाथ व्यपवर्तन में नहर का कार्य, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, केन्द्रीय विद्यालय, पेण्ड्री में आवासहीन परिवारों के लिए आवास, सूखा मुआवजा राशि और पेयजल के लिए कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की जनता ने शहर के विकास का सपना देखा था, उस सपने के अनुरूप इस शहर को बनाने का काम किया जा रहा हंै। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने पूरे देश के भीतर विकास की नई दिशा तय की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के साथ-साथ राजनांदगांव शहर के भीतर भी वैसा ही विकास दिखेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम राजनांदगांव द्वारा जो भी प्रस्ताव लेकर पार्षदगण राज्य शासन के पास जाएंगे, उसे स्वीकृत कर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरूआत पार्षद से हुई है और मैं आज भी अपने आप को पार्षद समझता हूं। पार्षद विकास की मूल कल्पना को साकार करते हैं, उसे अपने वार्डों में क्रियान्वित करने की सबसे ज्यादा जवाबदारी होती है।

उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरूण साव ने राजनांदगांव शहर के विभिन्न विकास कार्यों के भूमिपूजन के अवसर पर सभी नगरवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव प्रदेश की संस्कारधानी है और इसका विकास नाम के अनुरूप होना चाहिए, जिसका अनुसरण प्रदेश में हो और शहर के विकास को देखकर अन्य शहर भी प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि केवल भवन बनाने से शहर का विकास संभव नहीं है। शहर के विकास के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। श्री साव ने कहा कि संस्कारधानी के समग्र विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करें, जिसके लिए शासन द्वारा हर संभव सहायता की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव स्वच्छ, सुंदर, सर्व सुविधापूर्ण, सुव्यवस्थित शहर बनाने तथा भू-जल के गिरते स्तर और पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए वाटर हावेस्टींग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता है। स्वच्छता एवं सुंदरता के मामले में राजनांदगांव शहर प्रदेश के अग्रणी शहरों में शामिल हो, इसके लिए नगरवासी संकल्प लेकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक एवं कचरे के उचित प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रसासों में सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों के विकास के लिए 1500 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। राजनांदगांव शहर के विकास के लिए आगामी जो भी योजनाओं के प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा उसे स्वीकृत किया जाएगा।

कार्यक्रम को सांसद श्री संतोष पाण्डे एवं महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती गीता साहू, पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव, श्री खूबचंद पारख, श्री सचिन बघेल, श्री भरत वर्मा, श्री संतोष अग्रवाल, श्री रमेश पटेल, नेता प्रतिपक्ष श्री किशुन यदु, श्री हरिनारायण धकेता, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री राजेन्द्र गोलछा, नगर पालिक निगम राजनांदगांव के पार्षदगण, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, आयुक्त नगर निगम श्री अभिषेक गुप्ता, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ग्राम बरगा में वृक्षारोपण महाभियान तथा 'एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत किया पौधरोपण

ग्रामवासियों को मिल पानी की समस्या से राहत

राजनांदगांव(प्रदेश रुचि)। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बरगा में वृक्षारोपण महाभियान तथा 'एक पेड़ माँ के नाम अंतर्गत पौधरोपण किया एवं परकोलेशन टैंक में इंजेक्शन वेल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत निःशुल्क पौधा वितरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधे वितरित किए। विधानसभा अध्यक्ष ग्रामवासियों से रूबरू हुए और उनसे से गांव की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पौधरोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, सभी ग्रामवासी इस कार्य के लिए आगे आएं। इसके साथ ही जल संरक्षण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि पेयजल की उपलब्धता बनी रहे। शासन के साथ ही उद्योगपति, स्वयंसेवी संस्थान हम सभी को मिलजुल कर पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर कार्य करना है, जिससे राजनांदगांव जिले के भू-जल स्तर में वृद्धि हो सके तथा स्वच्छ पर्यावरण सभी को मिल सके। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने उन्हें मिशन जल रक्षा अंतर्गत किए जा रहे कार्य तथा परकोलेशन टैंक में इंजेक्शन वेल के संबंध में जानकारी दी। स्वसहायता समूह की श्रीमती ज्योति भारद्वाज ने मिशन जल रक्षा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पहले गांव में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बोर कराने से तथा मनरेगा अंतर्गत मिनी परकोलेशन टैंक के निर्माण के बाद भू-जल स्तर में वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीणों को राहत मिली है। श्रीमती ज्योति भारद्वाज ने इसके लिए शासन को धन्यवाद दिया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को जानकारी देते हुए कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले भर में मिशन जल रक्षा अंतर्गत पौधरोपण के साथ ही जल संरक्षण के प्रति जनसामान्य में जागरूकता लाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम की सोच के साथ पौधे लगाने के लिए सभी को प्रेरित किया गया तथा पौधों के संरक्षण के लिए निःस्वार्थभाव से सेवा कार्य करने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि इंजेक्शन वेल द्वारा परकोलेशन टैंक में किए गए बोर ड्रिल के संबंध में आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों से चर्चा की गई। परकोलेशन टैंक में गांव की सभी महिलाओं ने मनरेगा अंतर्गत कार्य किया है तथा अब यहां इंजेक्शन वेल बनने पर गांव के भू-जल स्तर बढ़ेगा तथा जल जीवन मिशन अंतर्गत किए गए बोर का जलस्तर भी बढ़ेगा। जिससे गांव में गर्मी के दिनों में हो रही पानी की समस्या से निजात मिलेगी। रिचार्ज शाफ्ट बोरवेल सैंड फिल्टर के निर्माण की जानकारी दी गई। जिसमें असफल बोर को रिचार्ज करने की पद्धति अंतर्गत पहले एक सैंड फिल्टर का निर्माण किया गया। जिसमें पानी छानकर बोरवेल वाले चेंबर में जाएगा। जहां बोरवेल के छिद्र नुमा केसिंग से सीधे ग्राउंडवाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। जिससे आसपास के क्षेत्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी साहू, श्री सचिन बघेल, श्री रमेश पटेल, श्री संतोष अग्रवाल, श्री अशोक देवांगन, श्री सुर्यकांत भंडारी, श्रीमती प्रतीक्षा भंडारी, श्रीमती पुष्पा गायकवाड़, श्री कुमार सोनवानी, श्री लीलाधर साहू, श्री रोहित चंद्राकर, अन्य जनप्रतिनिधि, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री खेमलाल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

जब लेफ्टिनेंट कर्नल ने मेरी गोद में तोड़ा दम

टाइगर हिल के हीरो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर

भारत हर साल 26 जुलाई की तारीख को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। देश इस साल कारगिल विजय के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती मना रहा है। कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के दो वीरों, कैप्टन विक्रम बत्रा और सिपाही संजय कुमार ने परमवीर चक्र का सर्वोच्च सम्मान अर्जित किया था। इस युद्ध भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य दिखाकर पाकिस्तानी सेना को हराया था। कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में हिस्सा लेने वाले ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर ने युद्ध से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं। आपको बता दें कि तब खुशाल ठाकुर (रिटायर्ड) 18 ग्रेनेडियर्स में कर्नल और कमान अधिकारी थे जिन्होंने टाइगर हिल पर फतह हासिल की थी।

जब पलटन को को मिला मूव करने का आदेश

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि आज से 25 वर्ष पूर्व सन 1999 में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के भरोसे की हत्या की थी और कारगिल, दराज और बटालिक के इलाकों में घुसपैठ करके अपना कब्जा कर लिया था। जैसे ही भारतीय सेना को इसका आभास हुआ तभी से घुसपैठियों को मार भगाने की कवायद शुरू हो गई। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह कवायद एक भीषण युद्ध की शुरुआत है। मेरी यूनिट 18 ग्रेनेडियर जिसका मैं कमान अधिकारी था उन दिनों कश्मीर घाटी के मानसबल इलाके में तैनात थी। वहां पर आए दिन हमारी आतंकवादियों से मुठभेड़ होती थी। तैनात होने के कुछ ही दिनों में हमने 19 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। तभी हमें हमारे उच्च अधिकारियों से आदेश मिला कि पलटन को तुरंत दराज मूव करना है।

18 ग्रेनेडियर को मिला टोलोलिंग मुक्त कराने की जिम्मेदारी

दराज सेक्टर में दुश्मन ने टोलोलिंग, टाइगर हिल और मास्को घाटी में सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया था। दुश्मन लेह लद्दाख व शियाचीन ग्लेशियर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सेना के मूवमेंट को बाधित कर रहा था। खुशाल ठाकुर ने बताया कि 18 ग्रेनेडियर को टास्क मिला कि टोलोलिंग की सभी चोटियों को हर कीमत पर दुश्मन से मुक्त कराया जाए। हमने एक बेहतर रणनीति के साथ टोलोलिंग पर बैठे दुश्मन पर धावा बोल दिया।

22 मई से 14 जून तक चला हमला

खुशाल ठाकुर ने बताया कि उस समय दुश्मन की तादात और उसकी तैयारी के विषय में सटीक सूचना का अभाव था। साथ ही हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी साजो समान और दूसरे सैनिक दस्तों, विशेषकर आर्टिलरी का बेहद अभाव था। यही कारण था कि हर दिन हमारा नुकसान हो रहा था। परंतु 18 ग्रेनेडियर के जांबाजों ने इन सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने हौसलों को मजबूत रखा और अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन पर लगातार हमले करते रहे। 22 मई को शुरू हुआ यह हमला 14 जून तक चला और इन 24 दिनों में हम सभी कठिन व दुर्गम चढ़ाई, खराब मौसम और दुश्मन की लगातार हो रही भीषण गोलाबारी का सामना करते रहे। इस लड़ाई में मेजर राजेश सिंह अधिकारी ने अपने प्राणों की आहुति दी जिन्हें मनोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

जब टीम के साथी ने हाथों में दम तोड़ा

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि एक हमले के दौरान जिसे मैं स्वयं लीड कर रहा था, उसमें मेरे उपकमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन को गोली लगी और उन्होंने मेरी ही गोद में उन्होंने दम तोड़ दिया। आर विश्वनाथन को उनके अदम्य साहस के

लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अंततः 12 जून को हमने 2 राजपूताना राइफल्स के साथ मिलकर टोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और साथ ही 14 जून को महत्वपूर्ण चोटी पर विजय हासिल की। टोलोलिंग की लड़ाई में हमारे दो अधिकारी, दो सूबेदार और 21 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। खुशाल ठाकुर ने बताया कि 18 ग्रेनेडियर के शौर्य को देखकर सेना के उच्च अधिकारियों ने एक बार फिर हमें एक और महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपा। यह था दराज सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण छोटी टाइगर हिल पर कब्जा करना। मैं और मेरी टीम एक बार फिर अपनी तैयारी में जुट गए। हमने टाइगर हिल का हर संभव दिशा से रीकॉन्सेंस किया और सभी टुकड़ियों के कमांडरों के सुझाव को शामिल करते हुए एक बेहद सटीक रणनीति बनाई।

टाइगर हिल पर चौतरफा हमला

कहानी को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि 3 जुलाई की रात को हमने टाइगर हिल पर चौतरफा हमला बोल दिया और सबसे कठिन रास्ते को चुना। जिस तरफ से जाना ना मुमकिन था हमारी D कंपनी और घातक प्लाटून ने टॉप पर पहुंचकर दुश्मन को एकदम भौचक्का कर दिया। पूरी रात एक भीषण घमासान युद्ध हुआ और हम टाइगर हिल टॉप पर अपना फुटहोल्ड बनाने में सफल हुए। इसके बाद हमने लगातार हमले जारी रखें और 8 जुलाई को हमने पूरे टाइगर हिल पर विजय पताका फहरा दी। इस लड़ाई में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की शौर्य गाथा आज हर बच्चा जानता है जिसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में हमारी यूनिट के 9 नौजवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से और कप्तान सचिन निंबालकर को वीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर ने शौर्य पदक जीतकर अपने आप में एक कीर्तिमान बनाया।

पाकिस्तान की सेना में मची खलबली

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने बताया कि जैसे ही टाइगर हिल पर हमने विजय पताका फहराई। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना में खलबली मच गई। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ युद्ध विराम की गुहार लगाने अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास भागे। परंतु हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेई ने साफ कह दिया कि जब तक पाकिस्तान के आखिरी घुसपैठी को हम भारत की सीमा से नहीं खदेड देते युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता।

527 जवानों ने दी प्राणों की आहूति

ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि कारगिल के इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने 527 रणबाकुरों को अपने प्राणों की आहूति देनी पड़ी। इसमें 52 योद्धा हमारे हिमाचल प्रदेश के थे। मुझे याद है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वे हिमाचल में एक प्रचारक थे। धूमल जी जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, उनके साथ लड़ाई के फ्रंट पर गए और अपने सैनिकों से मिले। 5 और 6 जून को उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया और 92 बेस हॉस्पिटल में घायल सैनिकों से मिलकर उनके साथ मिठाई बांटी।

नौजवान स्वतंत्रता के मोल को समझें

कारगिल की लड़ाई से एक बार फिर साबित हो गया था कि भारत एक शांतिप्रिय देश है लेकिन अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख उठायेगा तो भारत की सशस्त्र सेनाएं उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए हमेशा मुस्तैद है। ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने कहा कि नौजवानों से बस यही कहना चाहूंगा कि वह इस स्वतंत्रता के मोल को समझें और भारत देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए अपने आप को सशक्त बनाएं, कुशल बनाएं और स्वावलंबी होकर भारत के विकास में अपना योगदान दें।

कारगिल युद्ध में भारत की विजय गाथा कई जांबाजों की कुर्बानी का सार है। ये कोई आम गाथा नहीं है। इसमें दर्द की छुअन भी है तो विजय का उल्लास भी। कारगिल युद्ध में विजयी दिलाने में कई जांबाजों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। इनमें एक नाम सुनील जंग का भी शामिल है। रायफलमैन सुनील जंग उन योद्धाओं में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि देश के लिए मर मिटना है। महज 8 साल की उम्र में ही एक स्कूल प्रतियोगिता में उन्होंने कह दिया था- देश के लिए खून का एक-एक कतरा बहा दूंगा। सुनील की ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स का सीना गर्व से चौड़ा गया था।

स्कूल प्रतियोगिता की वो कहानी...

8 साल की उम्र में जिस फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में सुनील शामिल हुए थे, उसके लिए उन्होंने जिद करके अपने लिए फौजी की ड्रेस खरीदी थी। फिर उन्होंने अपनी मां से कहा कि वो बंदूक भी लेंगे। मां ने उन्हें एक प्लास्टिक की बंदूक लेकर भी दे दिया। इसके बाद प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने कई देशभक्ति गीत गाए। बताया जाता है कि सुनील के पिता नर नारायण जंग महत भी गोरखा बटालियन में थे और दादा मेजर नकुल जंग भी ब्रिटिश काल में गोरखा रायफल्स में ही थे, जिससे उन्हें सेना में जाने की प्रेरणा मिली थी।

घरवालों को बिना बताए सेना में एंट्री-16 साल की उम्र में ही सुनील सेना में भर्ती हो गए थे। इसके बारे में उन्होंने अपने घरवालों को भी नहीं बताया था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी मां से कहा कि पापा और दादा की तरह ही मैं भी सेना में भर्ती हो गया हूं। सुनील को 11 गोरखा रायफल्स में तैनाती मिली थी। कारगिल जाने से पहले उन्होंने अपनी मां से कहा था-

नमन! देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले 2 Kargil Hero की प्रेम कहानी

पूरा देश आज कारगिल युद्ध (Kargil War) के दो हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैय्यर (Captain Vikram Batra and Captain Anuj Nayyar) की देशभक्ति को कृतज्ञ होकर नमन कर रहा है. कारगिल युद्ध में देश की जीत के इन दो प्रमुख नायकों ने सात जुलाई, 1999 को अपना सर्वोच्च बलिदान (Martyrdom Day) किया था. शौर्य और पराक्रम में तो भारतीय सेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है. 24-25 साल की उम्र में युद्ध भूमि में संघर्ष करते हुए देश के लिए वीरगति पाने वाले दोनों ही नायकों की प्रेम कहानी भी कम रोचक नहीं है. आइए, आज इन दोनों ही नायकों के जीवन से जुड़े इस पक्ष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.

कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेमिका का बलिदान

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी को लोग कभी भूल नहीं सकते. इसके साथ ही उनकी प्रेमिका का बलिदान भी हमेशा याद रखने लायक है. कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी प्रेमिक डिंपल चीमा की कहानी पर बॉलीवुड में एक फिल्म शेरशाह भी बनी है. कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान होने के बाद उनकी प्रेमिका डिंपल चीमा ने आज तक शादी नहीं की है. वह अब भी कुंवारी हैं और पंजाब में एक शिक्षिका के रूप में देश का भविष्य गढ़ रही हैं.

कॉलेज में पहली मुलाकात का प्यार

पंजाब यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में साल 1995 में विक्रम बत्रा और डिंपल चीमा की पहली मुलाकात हुई थी. पहली ही मुलाकात से दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे थे. डिंपल बत्रा ने कई बार अपने रिश्ते के बार में मीडिया से बात करते हुए इसकी चर्चा की है. उन्होंने कहा है कि मैं विक्रम से पहली बार 1995 में चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में मिली थी. हम दोनों अंग्रेजी विषय में एमए करने आए थे. हम दोनों ही किसी कारण से अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए थे. लगता है कि नियति को कुछ और ही मंजूर था, वो हमें साथ लाने की कोशिश कर रहे था. डिंपल ने कहा था कि हम दोनों अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे.

विक्रम-डिंपल की प्रेम कहानी के अनछुए पहलू

डिंपल चीमा ने बताया कि हम दोनों हमेशा मंसा देवी मंदिर और गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब जाते रहते थे. एक दिन हम गुरुद्वारा में परिक्रमा कर रहे थे और वह मेरे पीछे-पीछे मेरा दुपट्टा पकड़ कर चल रहा था. जब हमारी परिक्रमा पूरी हुई तो, उसने मुझे कहा, 'बधाई हो मिसेज बत्रा. हमने साथ में फेरे ले लिए... ये चौथी परिक्रमा है.'

कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी पोस्टिंग पर थे. उस दौरान डिंपल पर परिवार वाले शादी के लिए दबाव बना रहे थे. पोस्टिंग से विक्रम लौटे तो डिंपल ने उनको ये बात बताई. विक्रम ने फौरन फिल्मी स्टाइल में अपने पर्स ने ब्लेड निकाला और अंगूठा काट कर डिंपल की मांग भर दी. डिंपल ने उस पल को याद करते हुए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बताती हैं. कारगिल युद्ध से आने के बाद कैप्टन विक्रम और डिंपल की शादी होनेवाली थी. विक्रम ने अपने घर पर भी सबको ये बात बता दी थी कि वो डिंपल से शादी करना चाहते हैं. डिंपल ने बताया था कि कारगिल के जंग पर जाने से पहले विक्रम ने कहा था कि वहां से आने के बाद हम शादी करेंगे. डिंपल इस उम्मीद में थी कि वह दुल्हन बनेंगी, लेकिन विक्रम तिरंगे में लिपटकर आए. इसके बाद डिंपल ने आज तक शादी नहीं की है. उन्होंने विक्रम की याद में सारी जिंदगी बिताने का फैसला किया है.

कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नैय्यर का बलिदान

टाइगर हिल के पश्चिम में प्वाइंट 4875 के एक हिस्से पिंपल कॉम्प्लेक्स को खाली कराने की जिम्मेदारी 17 जाट रेजिमेंट के

कैप्टन अनुज नैय्यर को दी गई. प्वाइंट 4875 की यह पोस्ट 6000 फुट की ऊंचाई पर थी, जिसे जीतना बेहद जरूरी था. कदम-कदम पर मौत से सामना करते हुए बढ़ते कैप्टन अनुज ने अकेले ही पाकिस्तान के नौ घुसपैठियों को मार गिराया और बाकी को पीछे खदेड़ दिया. घायल कैप्टन अनुज नैय्यर ने मशीनगन से बंकर को भी तबाह कर दिया था. विजय का तिरंगा फहराने के लिए वह आगे बढ़ रहे थे कि दुश्मन का एक ग्रेनेड सीधा उनपर पड़ा और वह वीरगति को प्राप्त हो गए. इस बीच पाकिस्तानी घुसपैठियों ने वापस आकर प्वाइंट 4875 पर कब्जा करना चाहा, लेकिन पीछे से दूसरी टीम के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा पहुंच चुके थे. उन्होंने घुसपैठियों का काम तमाम कर दिया, लेकिन तिरंगा फहराने से पहले वह भी दुश्मन की गोलियों की बौछार से बलिदान हो गए. हालांकि प्वाइंट 4875 पर 7 जुलाई को ही भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया गया.

कैप्टन अनुज ने युद्ध से पहले भेजनी चाही अंगूठी

करगिल युद्ध में अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार महावीर चक्र विजेता कैप्टन अनुज नैयर की सगाई हो चुकी थी. बलिदान होने तक तय था कि युद्ध से लौटकर यानी दो महीने बाद शादी होने वाली है. कारगिल युद्ध के दौरान ही अनुज नैयर को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया था. अनुज अपनी बचपन की दोस्त सिमरन से सगाई के लिए घर जाने वाले थे. उसी बीच कारगिल युद्ध छिड़ गया. उन्हें मोर्चे पर कारगिल जाना पड़ा. कैप्टन अनुज नैय्यर ने युद्ध के लिए जाते वक्त अपने सीनियर को एक अंगूठी दी और कहा था कि उनकी मंगेतर को दे दें.

साथ पढ़े थे अनुज - सिमरन दस साल से प्यार

कैप्टन अनुज की मां मीना नैयर के मुताबिक अनुज अपने साथ पढ़ी एक लड़की को पसंद करता था. दोनों दस साल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों की सगाई हो गई थी और शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी. 10 सितंबर 1999 को अनुज की शादी होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अनुज अपनी मां से जंग की बातें शेयर नहीं करते थे. उन्हें बाद में पता चला था कि वह भी कारगिल युद्ध में शामिल है.

पिता को लिखे आखिरी खत में युद्ध से जुड़ी बात

कैप्टन अनुज अपने पिता एसके नैयर से युद्ध की बात शेयर करते थे. उन्होंने कहा था कि बेटा जंग में हो, कुछ भी हो जाए कभी दुश्मन को अपनी पीठ नहीं दिखाना. कैप्टन अनुज नय्यर ने जंग पर जाने से ठीक पहले लिखी आखिरी चिट्ठी में अपने पिता को लिखा था कि डियर डैड, डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है. आप 200 प्रतिशत सही थे, जमीनी हवा कुछ नहीं छुपाती. आप चिंता मत कीजिए. आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकते. मुझे सिर्फ आपकी चिंता लगी रहती है. आप लोग अपना ध्यान रखें. आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ मनाएंगे.

तिरंगे में लिपटे अनुज के साथ घर लौटी अंगूठी

सीनियर ने कैप्टन अनुज से कहा कि तुम खुद लौटकर देना. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूं वापस लौटूंगा या नहीं. लौट आया तो खुद दे दूंगा. वरना आप इसे मेरे घर भेज देना और मेरा संदेश दे देना. वे नहीं चाहते थे कि उनके प्यार की निशानी दुश्मन के हाथ लगे. इस जंग से कैप्टन अनुज नैय्यर का पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटा हुआ दिल्ली पहुंचा तो परिवार के साथ ही सिमरन फूट-फूटकर रो रही थी. अनुज की शहादत के बाद उनके शव के साथ वह अंगूठी भी उनके घर पहुंची थी.

विष्णु के सुशासन में दिव्यांगों को मिल रही सुविधा

रायपुर (प्रदेश रुचि)

छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं लागू हुई है। राज्य के निःशक्तजनों के लिए सरकार सहारा बन रही है। जिसके समाज कल्याण विभाग के माध्यम से राहत पहुंचाने का कार्य हो रहा है। निराश्रित, बुजुर्ग एवं दिव्यांग हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाओं पर काम हो रहा है। जिला कांकेर, ग्राम गोतपुर आवास पारा निवासी 13 वर्षीय कुमारी वर्षा 80 प्रतिशत दिव्यांग है और चलने-फिरने में अक्षम है। उसे कहीं भी जाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब उसकी राहे आसान हो गई है और वह अपना सफर पूरा करने के लिए खुद सक्षम है। क्योंकि समाज कल्याण विभाग द्वारा व्हील चेयर प्रदान किया गया। व्हील चेयर मिल जाने से अब उन्हें गांव से बाहर आने-जाने में आसानी होगी। समाज कल्याण विभाग की अधिकारी श्रीमती क्षमा शर्मा ने बताया कि दिव्यांग वर्षा के पिता श्री कमलेश के द्वारा व्हीलचेयर प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए समाज कल्याण कार्यालय परिसर में व्हीलचेयर प्रदान किया गया।

जशपुर को पर्यटन नक्शे में शामिल करने मुख्यमंत्री ने की बड़ी पहल

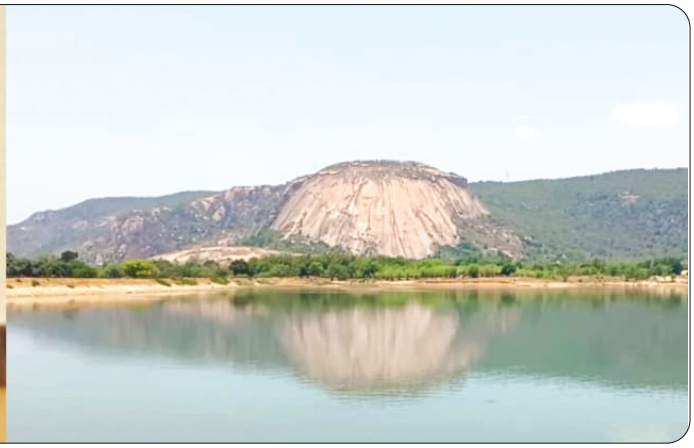

जशपुरनगर (प्रदेश रुचि)

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल से जिले के प्रसिद्ध प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल मयाली को पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण में शामिल कर लिया है। इस योजना में शामिल हो जाने से पर्यटन स्थल में बुनियादी सुविधाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। साथ ही इसके प्रचार प्रसार होने से यहां पर्यटकों की हलचल बढ़ने की संभावना भी है।

उल्लेखनीय है कि मयाली नेचर कैम्प,जिले के कुनकुरी ब्लाक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे में स्थित है। बेलसोंगा डेम और एशिया की सबसे उंचा शिवलिंग माना जाने वाला मधेश्वर पहाड़ का विहंगम मनमोहक दृश्य पर्यटकों को घंटों समय व्यतीत करने का अवसर देता है। वनविभाग ने इस स्थल पर पर्यटकों की सुविधा के लिए टेंट की व्यवस्था भी की है। इन टेंट हाउस में डेम के किनारे,हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर रात्रि विश्राम का परिवार के साथ आनंद उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक जुटते हैं। विशेष कर विकेंड के दिनों में यहां पर्यटकों की हलचल अधिक रहती है। पर्यटकों को मयाली नेचर कैंप में बोटिंग का आनंद उठाने की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए गाइड के साथ सुरक्षा के सभी इंतजाम किये गए हैं। राज्य सरकार के सहयोग से मयाली नेचर कैम्प में कैकट्स गार्डन का विकास भी किया जा रहा है। इस विशेष गार्डन में देश भर में पाएं जाने वाले कैक्ट्स की प्रजातियों को समेटा गया है ताकि युवा पीढ़ी कैम्टस से भली भांति परिचित हो सके। इसका एक उद्देश्य लोगों को बायोडायर्वसिटी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन करते हुए,विकास के लिए एक्शन प्लान और डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

कलेक्टर ने बरसते पानी में विभिन्न ग्रामों में दौरा कर विकास कार्यों का लिया जायजा

बालोद (प्रदेश रुचि)

कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आज बरसते पानी में जिले के डौण्डी विकासखण्ड के वनांचल के विभिन्न ग्रामों का दौरा कर वहाँ चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले में लगातार हो रहे बारिश के फलस्वरूप उत्पन्न स्थिति का भी अवलोकन किया। कलेक्टर चन्द्रवाल ने डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम ओड़गांव में पहुँचकर डेयरी पालक कृषक रामचंद्र राजपूत के डेयरी में पहुँचकर दुग्ध उत्पादन के कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर चन्द्रवाल ने पशु पालक कृषक रामचंद्र राजपूत से बातचीत कर उनके डेयरी में कुल पशुओं की संख्या एवं प्रतिदिन होने वाले दुग्ध उत्पादन के संबंध में जानकारी ली। मौके पर उपस्थित पशु पालन विभाग के उप संचालक ने बताया कि कृषक रामचंद्र राजपूत को राज्य शासन के डेयरी उद्यमिता विकास योजना से लाभान्वित किया गया है। चन्द्रवाल ने पशुपालन विभाग के उपसंचालक को ओड़गांव एवं आसपास के अन्य कृषकों को भी डेयरी पालन की जानकारी देने तथा राज्य शासन के डेयरी उद्यमिता विकास योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिससे की वनांचल के पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके एवं समुचित मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो सके। चन्द्रवाल ने पशुपालन के उप संचालक को घोटिया अंचल के पशुपालकों के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले दुग्ध को जिला मुख्यालय बालोद में स्थित दुध गंगा तक पहुँचाने हेतु परिवहन की भी उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

चन्द्रवाल ग्राम ठेमाखुर्द में पहुँचकर अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीणों से चर्चा कर ग्राम ठेमाखुर्द में जल जीवन मिशन के कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। सरपंच एवं ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम ठेमाखुर्द में जल जीवन मिशन का कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी घरों में समुचित मात्रा में पानी पहुँचने की जानकारी दी। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को जल जीवन मिशन के कार्यों का सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान चन्द्रवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ठेमाबुजुर्ग में पहुँचकर उपस्वास्थ्य केन्द्र के व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपस्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चंद्रिका साहू से अस्पाल में प्रतिदिन आने वाले मरीजों एवं टीकाकरण के लिए कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या एवं प्रसुति आदि के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्वास्थ्य केन्द्र के ओपीडी, स्टोर रूम, टीकाकरण कक्ष आदि का भी अवलोकन किया। कलेक्टर चन्द्रवाल ग्राम पचेड़ा में पहुँचकर जैविक खेती करने वाले किसानों से बातचीत कर ग्राम पचेड़ा एवं आसपास के ग्रामों में जैविक खेती के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्राम पचेड़ा के किसानों को जैविक खेती योजना अंतर्गत कृषि आदान सामग्रियों का भी वितरण किया। इसके अंतर्गत कलेक्टर ने किसानों को खरपतवार नियंत्रण हेतु हस्तचलित यंत्र पैडीवीडर एवं किटनाशक, फफूंदनाशक आदि विभिन्न किटनाशक दवाइयां प्रदान की। उन्होंने मौके पर उन्होंने मौके पर उपस्थित कृषि विभाग के अधिकारियों को कीटनाशक दवाइयों की प्रयोग की जानकारी किसानों को प्रदान को कहा। इस मौके पर उप संचालक कृषि एसएन ताम्रकार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीडी मण्डले सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

गुरु का स्थान समाज में सर्वोच्च व अत्यंत सम्मानीय : कलेक्टर

बालोद (प्रदेश रुचि)। कलेक्टर चन्द्रवाल ने कहा कि प्राचीन काल से ही हमारे समाज में गुरू का स्थान सर्वोच्च एवं अत्यंत सम्मानीय है। कलेक्टर चन्द्रवाल ने कहा कि हमारे मनिषियों ने गुरू की तुलना ईश्वर से कर समाज में गुरू की महत्ता व प्रासंगिकता को रेखांकित किया है। कलेक्टर चन्द्रवाल सोमवार 22 जुलाई को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल बालोद में आयोजित गुरू पूर्णिमा समारोह में अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। कलेक्टर चन्द्रवाल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर उन्होंने

अनादि काल से लेकर आज तक राष्ट्र के निर्माण में पूज्य गुरूओं के अवदानों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुरू एवं शिक्षक राष्ट्र एवं समाज के निर्माता होते हैं। जो विद्यार्थी रूपी कच्ची मिट्टी को एक जिम्मेदार नागरिक एवं बेहतर इंसान के रूप में सुंदर स्वरूप में सुंदर स्वरूप में ढालते हैं। चन्द्रवाल ने कहा कि एक योग्य, निष्ठावान एवं समर्पित शिक्षकों का राष्ट्र व समाज के प्रति योगदान अत्यंत अतुलनीय है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकों, अतिथियों एवं विद्यार्थियों को गुरू पूर्णिमा के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को अपने माता-पिता, गुरूओं तथा बड़े-बुजुर्गों का मन से सदा सम्मान करने एवं इनके बताएं हुए रास्तों पर चलने को कहा। चन्द्रवाल ने विद्यार्थी जीवन को व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण कालखण्ड बताते हुए सभी विद्यार्थियों को परिश्रम एवं लगन के साथ-साथ पूरे मनोयोग से विद्या अध्ययन कर जीवन में उपलब्धि हासिल करने की सीख दी। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों की यशस्वी एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में शाला परिवार के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल, श्रीफल भेंटकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारी पीसी मरकले एवं अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। समारोह में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के सहायक परियोजना अधिकारी अनुराग द्विवेदी सहित संस्था के प्राचार्य अरूण कुमार साहू एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना हम सभी का सौभाग्य : श्रद्धालुगण

बालोद। भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या धाम जाना हम सभी का सौभाग्य है, बरसों पूराना हमारा यह सपना आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरा कर रहे हैं। श्री रामलला दर्शन के लिए अयोध्या के लिए प्रस्थान करने के पूर्व श्रद्धालुओं ने कहा कि इस योजना के तहत हम श्रद्धालुओं को भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले छत्तीसगढ़ सरकार को हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि जिले के ग्राम झलमला स्थित समाज कल्याण विभाग के कार्यालय परिसर से जिले के 77 श्रद्धालुओं का दल आज श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा आज सुबह समाज कल्याण विभाग कार्यालय परिसर से श्रद्धालुओं को बस के माध्यम से दुर्ग रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया। जहाँ से वे योजना के तहत् संचालित रेल के माध्यम से अयोध्या हेतु प्रस्थान करेंगे। श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना के तहत अयोध्या जा रहीं बालोद के आमापारा निवासी प्रतिभा यादव ने राज्य शासन की इस योजना की भूरी-भूरी सराहना की है। उन्होंने कहा कि वे शासन की इस योजना से बहुत खुश हैं इसके माध्यम से अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने की बरसों पुरानी उसकी ईच्छा पूरी होनी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह प्रतिदिन रामायण पाठ करती हैं। प्रतिभा यादव अपने अयोध्या धाम की यात्रा को लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की सराहना ग्राम टेकापार के श्रद्धालु शत्रुघन साहू, खुबलाल साहू और बलदाऊ साहू ने भी की है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि वे आज इस योजना के माध्यम से अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव से बड़ी संख्या में लोगों ने अयोध्या जाने हेतु आवेदन किया है, जिसमें उनका चयन अयोध्या जाने के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार उन्हें भगवान के घर का दर्शन करा रही है, जिससे वे बहुत खुश हैं। इसी प्रकार बालोद की द्रौपति पवार और संतोषी ने कहा कि हम घरेलु महिलाएं और हमेंशा घर के कार्यों में व्यस्त रहती हैं।

पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइलमेन की पुण्यतिथि पर अल्पसंख्यक मोर्चा ने दी श्रद्धांजलि

बालोद (प्रदेश रुचि)।भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि शनिवार को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा पुण्य स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भाजपा जिला कार्यालय जुंगेरा बालोद में रखा गया। इस आयोजन में भाजपा जिले के वरिष्ठ नेता गणों की उपस्थिति में उनके तेल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही इस दिन को यादगार बनाने अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष अकबर तिगाला के नेतृत्व में जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण तथा एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण किया गया । इस दौरान अकबर तिगाला ने डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए उपस्थित अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष नेताओं का स्वागत उद्बोधन किया। तो वही इस दौरान जिले भर के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइलमेन जीवनी पर प्रकाश डालते हुए सभी को उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कहते दिखे.इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन साहू, वरिष्ठ नेता कृष्णकांत पवार ,प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, वरिष्ठ नेता यज्ञ शर्मा, महामंत्री राकेश छोटू यादव, चेमन देशमुख,उपाध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल, मंत्री शरद ठाकुर,कृतिका साहू , जिला कार्यालय प्रभारी लोकेश श्रीवास्तव, जिला प्रभारी हमीद अहमद खान,सह प्रभारी काफिलुददीन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अब्दुल इब्राहिम, जिला अध्यक्ष अकबर तिगाला, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र साहू, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम साहू,जिला उपाध्यक्ष इमरान खान, जावेद तिगाला, फिरोज कुरैशी, असरार अहमद, वीरेंद्र साहू, वसीम तिगाला, श्रीमती खुर्शीद सिद्दीकी, गजेंद्र यादव, संतोष साहू, नदीम बडगूजर, रमेशजैन, नरेंद्र लुंकड़, राजू भंसाली, ने जिला चिकित्सालय में जाकर सैकड़ो मरीजों को फल , बिस्किट वितरण किया, एवं वहां के मरीजों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

पेश है
www.licindia.in
एलआईसी का
जीवन उत्सव
Plan No.: 871
UIN: 512N363V01
उत्सव
मनाने का
गारंटीड तरीका
आजीवन गारंटीड रिटर्न
के साथ
पूर्ण आयु जीवन बीमा एवं लाभ भुगतान के विकल्प
● सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष
● प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत वृद्धि
● नियमित आय लाभ / फ्लेक्सी आय लाभ
● न्यूनतम मूल बीमा राशि 5 लाख
एक नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग, व्यक्तिगत, बचत, पूर्ण आयु जीवन बीमा योजना
ऑनलाइन ख़रीदें
LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
हर पल आपके साथ
LIC/P1/2023-24/13/Hin
बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों,नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़े.
हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512
संतोष कुमार साहू
अभिकर्ता- भारतीय जीवन बीमा निगम व स्टार हेल्थ
मो.नं.9893162815